RAJYA SABHA

Friday, the 16*th December*, 2005/25 *Agrahayana*, 1927 (*Saka*)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*341. *[The questioners (Shrimati Ambika Soni and Shri Anand Sharma) were absent. For answer vide page* 29.*]*

*342 *[The questioner (Shri Silviu) Condpans was absent. For answer vide page* 31.*]*

Damage to onion crop in Maharashtra

*343. SHRI SANJAY RAUT:†
SHRI TARIQ ANWAR:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether heavy rains and floods in Maharashtra have caused extensive damage to onion crop in Maharashtra, if so, the extent of loss and damage to the crop;

(b) what percentage of demand for onion in the country is met by Maharashtra, and how far the recent onion crisis in the country was attributable to this damage; and

(c) what Central aid, if any, was sought and given to the Government of Maharashtra to help the farmers out of the crisis caused by such damage to onion crop?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sanjay Raut.

Statement

(a) to (c) Heavy rains and floods in Maharashtra have caused extensive damage to onion crops during this year (2005). During April-May, 2005, unseasonal rain and high temperature during harevesting time of rabi crop resulted in poor quality which was responsible for reduced shelf-life because of which quantity of onion stored, decreased by 25% in comparison to last year. Against 7 lakh tonnes stored in 2004, only 5.25 lakh tonnes could be stored in 2005. During July 2005, owing to continuous rains in Maharashtra, there was damage to the seed sown during early kharif, forcing the farmers to re-sow, causing production loss and delayed kharif crop in Maharashtra by about a month. Loss of nursery and delayed monsoon resulted in reduction of onion cropped area by about 15%. Again, during October, 2005, heavy rains damaged the kharif crop in some of the districts of Maharashtra. The overall loss in kharif production in Maharashtra is estimated to be about 43%. Against the production of 2.70 lakh tonnes in Khariff 2004, the production in Maharashtra during kharif, 2005 is 1.55 lakh tonnes.

The State of Maharashtra meets 28% of the total demand of onion in the country. As mentioned above, the unseasonal and excess rainfall is responsible for shortage in availability of onion and consequent price hike. This situation prevailed for a short period during the month of October 2005, which soon stabilized due to sufficient arrival of onion from Rajasthan and other Southern States.

Government of Maharashtra submitted a memorandum to the Central Government for the floods that occurred in July-August, 2005 indicating the total agricultural loss at Rs. 1239.57 crore. Memorandum of the State Government did not indicate crop-wise breakup of the losses. Government have approved release of an amount of Rs. 697.45 crore.

SHRI SANJAY RAUT: Sir, the hon. Minister, in his reply, has agreed that heavy rains and floods have destroyed the onion crops in Maharashtra. Maharashtra is the highest producer of onion in the country. The onion bulbs should necessarily be stored in spacious and ventilated structures, as they tend to spoil in cold-storages. Improper storage of onions makes them vulnerable to weather-related conditions. So, there is a need for creating more storage and allied facilities for onions, for which the Maharashtra Government needs the Central assistance. Is the

Government considering to provide special assistance to the Maharashtra Government for this purpose?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, there is a scheme under the NCDC. On the basis of the proposals sent to the NCDC by the State Governments, the NCDC provides them money to construct warehouses, godowns, and other special types of arrangements for the products, like, onion.

SHRI SANJAY RAUT: Sir, there is another problem, which is related to transportation. There is a need to have effective and good transportation facilities for onion. During the transportation, heavy losses of onions have been occurring due to non-availability of ventilated railway wagons. So, the Government should make available ventilated railway wagons at affordable rates. Is the Government making any efforts with the Railway Ministry, in this regard?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, there is no specific proposal like this. But we will certainly take it up with the Railway Ministry.

श्री तारिक अनवर: सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में काफी विस्तार से सारी बातों की जानकारी दी है। इन्होंने खुद अपने उत्तर में यह कहा है कि लगभग 43 प्रतिशत का नुकसान हुआ है और इससे किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। एक बार लोगों ने बुवाई की, उसके बाद फिर बारिश आने की वजह से नुकसान हुआ और उन्हें दोबारा बुवाई करनी पड़ी, जिसके कारण वहां किसानों की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार और कृषि मंत्रालय खासतौर से इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि किसानों ने खासकर प्याज की बुवाई के लिए जो लोन लिया है और जो नुकसान हुआ है, उसको माफ किया जाए? उसको माफ कराने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से क्या कोई पहल की जाएगी, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री शरद पवार: साधारणतया लोन माफ करने के लिए ऐसा कोई provision नहीं है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति होती है, उन्होंने बैंक से कुछ पैसे लिए होंगे, उसको re-schedule करने के लिए, हम उनको सहायता दे सकते हैं। इस बारे में कोई specific proposal राज्य सरकार की तरफ से अभी तक हमारे पास नहीं आया है। एक overall proposal आया था, जिसमें राज्य सरकार ने वहां मदद मांगने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें 1,240 करोड़ रुपए की डिमांड उन्होंने की थी, उसमें से अभी तक 697 करोड़ रुपए का एमाउंट राज्य सरकार को हमने sanction करके भेजा है, जिसमें खेती का जो नुकसान हुआ है, फसलों का जो नुकसान हुआ है, वह शामिल हैं, चाहें वह मूंगफली हो, चाहे प्याज हो, चाहे गन्ना हो, अलग-अलग जो फसलें हैं, उनके लिए सहायता देने का अधिकार राज्य सरकार को है और यह amount हमने उनको भेज दिया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: धन्यवाद, सभापति जी। सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहेंगे कि उन्हें मालूम है कि प्याज की फसल हमारे देश में इतनी महत्वपूर्ण है कि प्याज का संकट सरकारें गिरा देता है। 1980 में जनता पार्टी की सरकार प्याज पर गई, 1998 में दिल्ली की भाजपा की सरकार प्याज पर गई। यह संकट सबसे ज्यादा गरीबों को प्रभावित करता है, जो केवल रोटी प्याज खाते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगी कि....(व्यवधान)...

श्री सभापति: आगे गवर्नमेंट प्याज के कारण न जाए, वह बात कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। चूँकि यह संकट बार-बार उभरता है, तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगी कि क्या बड़े-बड़े वेयर हाउसेज़ बना कर प्याज को इकट्ठा करने की कोई योजना सरकार ने बनाई है, जिसके कारण जो प्याज ग्रोअर्स हैं, प्याज को उगाने वाले हैं, उनको भी अच्छा दाम मिल जाए, वे वेयर हाउस में चले जाएं और कभी भी जब कमी हो? तो गरीब को इसका दुष्प्रभाव न सहना पड़े। क्या इस तरह की कोई योजना मंत्री जी बना रहे हैं?

श्री शरद पवार: यह परिस्थिति बार-बार कभी पैदा नहीं होती। प्याज की परिस्थिति तो हमेशा अलग पैदा होती है कि आप पाँच साल का टोटल पीरियड देखिए, तो 2 साल या 3 साल किसानों के सामने इतनी बुरी परिस्थिति पैदा होती है, इतनी कम कीमत मिलती हैं कि उससे ज्यादा नुकसान होता है। पूरे देश में ओनियन के प्रोडक्शन की इतनी समस्या नहीं है। कभी तो ऐसी समस्या जरूर पैदा होती है, जिसकी कीमत आम कंज्यूमर को देनी पड़ती है, जो परिस्थिति इस साल पैदा हुई थी। ओनियन के स्टोरेज के बारे में कई लिमिटेशंस हैं। ओनियन एक ऐसा आइटम है, जिसे हम पूरे साल वहां रख सकते हैं या काल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। इसके लिए एक अलग तरह का इन्तजाम करना पड़ता है। जहाँ प्रोडक्शन होता है, वहाँ इसके लिए अलग तरह का इन्तजाम है। अभी खास तौर पर यह जो सवाल है, वह नासिक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है और नासिक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी फेसिलिटी बड़े पैमाने पर की है। कुछ और फैसिलिटीज़ के बारे में लोगों की डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए एनसीडीसी, बाकी जगह से हम आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हैं, जिससे इसका स्टोरेज हम ठीक तरह से कर सकेंगे और ऐसी परिस्थिति बाद में न हो जाए, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे।

SHRI JAIRAM RAMESH: Mr. Chairman, Sir, my question arises from the question asked by the hon. Member, Smt. Sushma Swaraj. Why are successive Governments just not able to import onions on time in order to depress prices when there are shortages? Irrespective of the Government and even though we are flushed with foreign exchange, there seems that we are not able to import onions, on time, to ensure lower prices.

Secondly, Sir what is the Government doing to reduce the dependence on one State? I know the hon. Minister comes from Maharashtra and he would not like dependence on Maharashtra to reduce prices, but the fact of the matter is that the extraordinary high level of dependence on Maharashtra for onions is causing distress to consumer every other year. Is there a plan for diversifying the base of onions production in the country?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, Maharashtra State onion production is hardly 28 per cent. The rest of the onion is produced in Gujarat, Bihar, Rajasthan, Karnataka, and many other States. So, it is not correct to say that there is dependence on Maharashtra only. It is true that a particular belt, that is, the Nasik belt produces substantial onions, but in the State, as a whole, that is not the situation.

जहाँ तक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात उठती है, इसमें एक बात मुझे सदन के सामने रखनी है कि इसके बारे में एक फर्म डिसिजन लेने का समय आया है। एक तो मैंने जैसा हमेशा कहा कि पाँच सालों में तीन साल सरप्लस प्रोडक्शन होता है। तीन हफ्ते पहले कर्नाटक में बंगलौर के आस पास किसानों ने, बिल्कुल दाम गिर गए, इसलिए अपने ट्रक से और ट्रैक्टर से प्याज लाकर सड़क पर फेंक दिया और ट्रैफिक वहाँ रुक गई थी। 15-20 दिन पहले ऐसी परिस्थिति कर्नाटक में पैदा हो गई थी। इसलिए हमारी एक लांग टर्म पॉलिसी होने की आवश्यकता है कि जिससे हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे और आवश्यकता हो तो हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। मगर जब ऐसी कुछ परिस्थिति यहाँ पैदा होती है कि जहाँ प्याज की कमी होती है, थोडे-बहुत रेट ऊपर जाते हैं, तो तुरंत सरकार के ऊपर भी प्रेशर आता है कि आप एक्सपोर्ट बन्द करो। इससे इन्टरनेशनल मार्केट में हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है और वहां काई हमारा प्रोडयूस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। साथ-साथ जरूरत पड़ी तो इम्पोर्ट करने की भी आवश्यकता होती है। ऐसी बारिश की वजह से सिर्फ तीन हफ्ते के लिए यह समस्या पैदा हुई थी और तब इम्पोर्ट करने की भी बात की गई थी। नाफेड को ऐसी सूचना भी दी गई थी। मगर दुनिया का, खास तौर पर पड़ोसी देश पाकिस्तान का जो रेट, जिस पा ट्रांसपोर्ट चार्ज हमें कम लगता था, वह रेट देखने के बाद यहां के प्राइस और वहां से प्याज यहां लाकर बेचने के लिए आने वाले खर्च में कोई फर्क नहीं था। इसलिए इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया जा सका।

SHRIMATI N.P. DURGA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether it is true that onion has not been included in the list of essential commodities under the Essential Commodities Act, 1955. As a result, the Government and NAFED have little control over the price of onion. If 'yes',

RAJYA SABHA [16 December, 2005]

at least, now, the hon. Minister can give us an assurance that onions would be included in the list of Essential Commodities so as to meet any future crisis.

at least, now, the hon. Minister can give us an assurance that onions would be included in the list of Essential Commodities so as to meet any future crisis.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, onion was one of the items which was included in the Essential Commodities list. There were more than 130 items which were included in that list. But, about four years back, a conscious decision was taken by the Government to reduce the list of essential commodities. That list has been reduced to about seven or eight items. A decision has also been taken to remove onion from that. It is not possible to include onion or these types of items in the Essential Commodities list.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, going by the answer, and, also the debate which took place yesterday on PDS, I would like to know from the hon. Minister regarding the post-harvest mechanism. We are very weak in post-harvest mechanism in respect of onions, limes, tomatoes, etc. As far as post harvest mechanism is concerned, what is the thinking of the Government? What are the programmes with the Government of India?

SHRI SHARAD PAWAR: In fact, I have given information to this august House that this is one of the serious problems which Indian farming community, is facing. As regards the losses, because of the non-availability of sufficient post-harvesting facilities, both, farmers and countries are losing very heavily. These losses are somewhat near to Rs. 50,000 crores per year. Onion is one of the items which is suffering because of that. Solution to this problem is to encourage setting up of dehydrogenation plants and factories. These factories should be set up where onion can be processed. The Agro Processing Ministry is giving encouragement and support to set up these types of projects. There are more projects which are in pipeline. There are one or two projects which are under erection.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: सभापति महोदय, यह प्रश्न मुख्य रूप से किसानों को फसल में जो नुकसान होता है, उससे संबंधित है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: क्वेश्चन करिए। आप कवेश्चन कर लीजिए।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: मैं यह जानना चाहता हूं कि किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए चाहे कोई भी फसल हो, प्याज हो या अन्य कोई और फसल हो, क्या सरकार पर युनिट पर किसान व्यापक बीमा योजना लाने का विचार रखती है?

श्री शरद पवार: सर, इस बारे में बीमा योजना का प्रस्ताव है और इसमें ऑनियन को भी स्वीकार किया गया है

*344. *[The questioner (Shri C. Perumal) was absent. For answer vide page 33.]*

Co-ordination Committee for agricultural development

*345. SHRIMATI VANGA GEETHA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have constituted the Agriculture Co-ordination Committee to focus on agricultural development and policy;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have set any time-frame to implement the recommendations of such Committee; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) An Agriculture Coordination Committee has been recently constituted under the Chairmanship of the Prime Minister, to evolve a systematic approach to policy formulation on issues pertaining to agriculture and to promote inter-sectoral and inter-departmental coordination in planning and implementation. The Composition of the Committee is as follows:

1. Prime Minister - **Chairman**
2. **Minister** for Agriculture and **Food & Civil Supplies & Consumer Affairs**
3. **Minister** of **Chemicals and Fertilizers**
4. Minister of **Finance**
5. **Minister for Commerce & Industry**
6. **Minister for Water Resources**